22 दिसम्बर, 2013

राजनैतिक अवसरवाद ने लोकप्रिय समर्थन का मुखौटा पहना

अरुण जेटली
(राज्य सभा में विपक्ष के नेता)

मेरे लिये जून 1975 से जनवरी 1977 तक देश में लगी आंतरिक आपात स्थिति का दौर बहुत कुछ सीखने वाला रहा। तब मैं छात्र था और बंदी बनाये गये युवाओं में शामिल था जिनको इमरजेंसी का विरोध करने के कारण 19 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। जेल में हम सबके लिये यह एक यक्ष प्रश्न था कि आखिरकार कितने दिन इमरजेंसी रहेगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लगातार अपनी तानाशाही, आपात स्थिति लगाने, प्रेस सेंसरशिप और राजनेताओं को बंदी बनाने को यह कहकर जायज ठहरा रही थीं कि 'अनुशासन के दौर' में कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। उनका दावा था कि भारत की जनता ने इसका समर्थन किया है। उन्हें यकीन था कि उन्होंने इमरजेंसी में जिस बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है वह काफी लोकप्रिय है। इस समर्थन को आंकने का कोई पैमाना नहीं था। लेकिन अपने राजनैतिक फैसले को आंकने का उनका एकतरफा नजरिया था। उन्होंने 1977 के अंत में इमरजेंसी को लोकप्रिय समर्थन हासिल होने के आधार पर आम चुनावों की घोषणा की। वह चुनाव में बुरी तरह पराजित हुईं। यहां तक कि उन्होंने अपनी सीट भी गंवा दी।

अत्यधिक प्रचार के अपने खतरे होते हैं। जनता को उकसाने वाला अपने तर्कों को अक्सर जायज ठहराता है। यूपीए सरकार अपनी तथाकथित उपलब्धियों के बड़े–बड़े विज्ञापनों को लेकर खुद भ्रमित हो गई।

<u>आम आदमी पार्टी</u>

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निश्चित तौर पर उत्कृष्ट रहा। उसका चुपचाप और सलीकेवाला अभियान रंग लाया। वह अपने विचारों को भुनाने में कामयाब रही जिसे बड़ी संख्या में जनता ने स्वीकार किया। वह वोट और सीट के लिहाज से भाजपा के बाद दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा बनी। जरूरी नहीं है कि त्रिशंकु विधानसभा को एक विफल विधानसभा माना जाये। अगर छोटी पार्टियां किसी बड़ी पार्टी का समर्थन करे तो सरकार बनाना संभव है। दिल्ली में आठ सीटें हासिल करनेवाली कांग्रेस संतुलन बनाने का काम कर सकती है। उसने आम आदमी पार्टी को सशर्त समर्थन देने की घोषणा की है।

आप ने साफ तौर पर कहा है कि वह वैकल्पिक राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है। वह विचारधाराओं से प्रेरित है। वह कांग्रेस या भाजपा का न तो समर्थन करेगी और न ही समर्थन लेगी। अगर

आप अपने सार्वजनिक रूख पर कायम रही तो दिल्ली विधानसभा का गतिरोध नहीं टूटेगा जिसके कारण उपयुक्त समय के बाद नये चुनाव कराने पड़ेंगे।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप वैकल्पिक राजनीति की अपनी प्रतिबद्धता से समझौता कर रही तो फिर वह कैसे खुद को न्यायोचित ठहरा पाएगी। आखिरकार विचारधारा से प्रेरित वैकल्पिक राजनीति में राजनीतिक अवसरवादिता के लिये स्थान नहीं होना चाहिये। आप इस बात से चिंतित हो सकती है कि उसके विधायक समेत कई विधायक जल्दी चुनाव नहीं चाहते हैं। सता हासिल करने के लिये यह रणनीति हो सकती है कि कुछ लोक लुभावन फैसले करें और फिर खुद को आगे के लिये तैयार कर लें। ऐसी तमाम रणनीति को अख्तियार करने के लिये आप को अपनी घोषित स्थिति से पलटी मारनी होगी। उसे कांग्रेस से समर्थन लेने के लिये जनता से किये गये वादे से पीछे हटना होगा। यही कारण है कि उसने फिर से जनमत संग्रह का ढकोसला किया। यह जनमत संग्रह खुद को स्थापित करने का उपाय मात्र है। ऐसी भीड को जमा किया जा रहा है जो उसे समर्थन दे। एक ही सवाल किया जा रहा है कि क्या आप को सरकार बनानी चाहिये।

जाहिर है, वे तो इस विचार से उत्साहित ही होंगे। आंकड़ों के लिहाज से चमत्कार ही है कि आप को चुनाव में 30 प्रतिशत से कम लोगों ने वोट दिया लेकिन 75 प्रतिशत से अधिक लोग चाहते हैं कि वह सरकार बनाये।

दरअसल राजनीतिक अवसरवादिता को लोकप्रिय समर्थन का मुखौटा पहनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिसमें उसके नेता यह दलील दे सकें कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेने जायेंगे। लेकिन हम लोकतांत्रिक हैं जो जनता की इच्छाओं के सामने झुक रहे हैं। वह तो जनता है जो चाहती है कि आप को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनानी चाहिये। क्या यह वैकल्पिक राजनीति की शुरूआत है या उसका अंत।